Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X (Print), Impact Factor: 7.866, Volume 15, No. 04(II), October-December, 2025, pp. 40-44

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के खेल संसाधनों एवं सुविधाओं का तुलनात्मक विश्लेषण

Mr. Gajendra Singh Naruka[1*] & Dr. Renu Shungloo[2]

[1]Research Scholar, IIS(deemed to University), Jaipur.
[2]Associate Professor & Head Department of Physical Education (Retd.), IIS(deemed to University), Jaipur.

[*]Corresponding Author: ptigajendranaruka@gmail.com

Citation: *Naruka, G., & Shungloo, R. (2025). ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के खेल संसाधनों एवं सुविधाओं का तुलनात्मक विश्लेषण. Journal of Modern Management & Entrepreneurship, 15(04 (II)), 40–44.*

सार

भारत जैसे विविधतापूर्ण, विशाल तथा जनसंख्या की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राष्ट्र खेलों के क्षेत्र में अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। खेल केवल मनोरंजन, अवकाश या प्रतियोगिता का साधन नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक गतिशीलता, सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय समरसता तथा व्यक्तिगत विकास का प्रभावी माध्यम भी हैं। खेल संसाधनों, अवसंरचनाओं और अवसरों का समान वितरण ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ आर्थिक संसाधनों की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और खेल सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है, वहीं शहरी क्षेत्रों में बेहतर खेल अवसंरचना, प्रशिक्षित कोच, तकनीकी साधन और संस्थागत समर्थन उपलब्ध होने के कारण खिलाडियों के विकास की संभावनाएँ अधिक होती हैं। इन परिस्थितियों से उत्पन्न असमानताएँ खेल विकास में एक गहरी खाई उत्पन्न करती हैं, जो न केवल खिलाडियों की प्रतिभा के प्रस्फुटन में बाधा बनती हैं, बल्कि राष्ट्रीय खेल प्रगति को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि खेल नीतियों का निर्माण संसाधन–समानता, समावेशिता और ग्रामीण–शहरी संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाए। समुचित नीति–निर्माण, सरकारी हस्तक्षेप, सामाजिक सहभागिता और तकनीकी उन्नति से ही खेलों को प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचाया जा सकता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल संसाधनों की उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता में विद्यमान विषमताओं का विश्लेषण करना है। यह विश्लेषण यह दर्शाता है कि खेल विकास तभी सम्भव है जब प्रत्येक नागरिककृचाहे वह किसी भी भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो कृ खेल सुविधाओं का समान रूप से लाभ उठा सके। अतः खेलों का सतत विकास तभी संभव है जब संसाधनों की समानता, अवसरों की समावेशिता और नीति–निर्माण में संतुलन को प्राथमिकता दी जाए।

शब्दकोशः *खेल अवसंरचना, संसाधन–विषमता, विकासात्मक असमानता, नीतिगत हस्तक्षेप, सामाजिक समावेशन।*

प्रस्तावना

खेल मानव जीवन की सबसे प्राचीन, सार्वभौमिक और विकासोन्मुख गतिविधियों में से एक है। यह केवल शारीरिक क्षमता, मानसिक अनुशासन और सामूहिक समन्वय का प्रतीक नहीं है, बल्कि समाज की सांस्कृ

[*] *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

तिक संरचना, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक प्रगति और मानव विकास का महत्वपूर्ण आधार भी है। सभ्यता के आरंभिक चरण से ही खेल मानव समाज का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। वर्तमान युग में खेलों का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह केवल मनोरंजन का माध्यम न होकर स्वास्थ्य संवर्द्धन, आर्थिक अवसर, सामाजिक एकता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रेरक बन चुका है। भारत जैसे विशाल एवं विविधताओं से परिपूर्ण देश में खेलों का विकास अनेक सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों, नीतिगत प्रक्रियाओं, संरचनात्मक व्यवस्थाओं और आधुनिक तकनीकों से प्रभावित होता है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ खेल के लिए आवश्यक अधोसंरचना, प्रशिक्षित कोच, अकादमिक खेल संस्थान, तकनीकी उपकरण, खेल विज्ञान प्रयोगशालाएँ तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन देखा जाता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। अधिकांश ग्रामीण प्रतिभाएँ पर्याप्त सुविधाओं, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग के अभाव में अपने कौशल का पूर्ण विकास नहीं कर पातीं। यह विषमता न केवल भौतिक संसाधनों की कमी का परिणाम है, बल्कि सामाजिक जागरूकता, नीति–निर्माण और संस्थागत भागीदारी में अंतर का भी संकेत देती है। शहरी क्षेत्रों में खेलों को पेशेवर करियर विकल्प, आर्थिक अवसर और जीवन–मान सुधार के रूप में देखा जाने लगा है, जबकि ग्रामीण संदर्भ में खेल अभी भी मुख्यतः मनोरंजन, सामुदायिक मेलजोल और सांस्कृतिक आयोजनों का हिस्सा बने हुए हैं। इसी कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच खेल अवसरों, सुविधाओं, प्रशिक्षण गुणवत्ता और खिलाडियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। यह असमानता खेल क्षेत्र में न केवल प्रतिभा के विकास को बाधित करती है, बल्कि राष्ट्रीय खेल प्रगति के मार्ग में एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है।

इस अध्ययन की भूमिका इसी अंतर को वैज्ञानिक, सामाजिक और नीतिगत दृष्टि से समझने, विश्लेषण करने और प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि खेल संसाधनों के वितरण में समता, अवसरों की समानता, समावेशिता, और ग्रामीण–शहरी संतुलन को स्थापित करने हेतु उपयुक्त निष्कर्ष एवं सुझाव प्राप्त किए जा सकें। इसके माध्यम से खेल क्षेत्र में विद्यमान विषमताओं को कम करके एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति -चाहे वह किसी भी भौगोलिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से हो समान अवसरों के साथ खेल विकास में भाग ले सके। इस अध्ययन का उद्देश्य इसी अंतर को वैज्ञानिक और नीतिगत दृष्टि से परखना है, ताकि खेल संसाधनों की समानता सुनिश्चित की जा सके।

साहित्य समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि खेल संसाधनों की विषमता भारतीय खेल संरचना की सबसे प्रमुख बाधा है।

सिंह और कौर (2018) ने अपने अध्ययन में पाया कि ग्रामीण किशोरों में खेलों के प्रति रुचि तो होती है, किंतु संसाधनों की कमी, विद्यालय स्तरीय खेल कार्यक्रमों की कमजोर स्थिति और प्रशिक्षकों के अभाव के कारण वे खेलों में नियमित भागीदारी नहीं कर पाते। इनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना की कमी प्रतिभाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।

वर्मा (2020) ने ग्रामीणदृशहरी क्षेत्र में खेल संसाधनों की असमानता का तुलनात्मक विश्लेषण किया। उनके अनुसार शहरी क्षेत्रों में खेल मैदान, जिमनैजियम, कोचिंग अकादमियाँ और खेल विज्ञान सुविधाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई गुना बेहतर हैं। यह अंतर न केवल आर्थिक संसाधनों का परिणाम है, बल्कि नीतिगत प्राथमिकताओं, निजी क्षेत्र के निवेश और सामाजिक जागरूकता के अंतर को भी दर्शाता है।

दत्ता और बनर्जी (2022) ने हाशिए पर स्थित समुदायों पर किए गए अध्ययन में बताया कि खेल विकास के मार्ग में सामाजिक भेदभाव, सांस्कृतिक प्रतिबंध, परिवारिक समर्थन का अभाव और आर्थिक बाधाएँ महत्वपूर्ण अवरोध हैं। इनका निष्कर्ष था कि खेल प्रतिभा केवल संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि सामाजिक संरचनाओं में मौजूद असमानताओं से भी प्रभावित होती है।

खान (2017) ने सरकारी नीतियों और खेल प्रबंधन की भूमिका का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि भारत में खेल नीति का उद्देश्य भले ही खेल विकास को तेज़ करना हो, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन में कई खामियाँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी, प्रशासकीय विलंब, और संसाधनों का केंद्रित वितरण खेल विकास को सीमित करता है।

पटेल (2019) के अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि जिले और ब्लॉक स्तर पर खेल सुविधाओं की उपलब्धता सीधे युवाओं की शारीरिक गतिविधियों, स्वास्थ्य और करियर विकल्पों पर प्रभाव डालती है। यह अध्ययन दर्शाता है कि जहाँ खेल सुविधाएँ बेहतर हैं, वहाँ के युवा अधिक सक्रिय, आत्मविश्वासी और प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं।

कुलकर्णी और जोशी (2021) ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित कोचों और विशेषज्ञों की कमी को सबसे बड़ी समस्या बताया। उनके अनुसार कोचिंग की गुणवत्ता खिलाड़ियों के प्रदर्शन और दीर्घकालीन विकास की मुख्य निर्धारक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर गैर–प्रशिक्षित या अल्प–प्रशिक्षित कोचों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

थॉमस और रॉय (2020) ने सामाजिक–आर्थिक बाधाओं का अध्ययन करते हुए पाया कि ग्रामीण युवा खेलों को करियर के रूप में अपनाने से इसलिए भी हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि खेल से स्थायी आय या सुरक्षित भविष्य प्राप्त करना सुनिश्चित नहीं है। इसके विपरीत, शहरी युवाओं के पास अधिक उदाहरण, सुविधाएँ और अवसर मौजूद होते हैं। इन अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि खेल संसाधनों में असमानता का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन पर पड़ता है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समान अवसर की अवधारणा को भी प्रभावित करता है।

शोध उद्देश्य

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खेल संसाधनों की उपलब्धता और उपयोगिता का तुलनात्मक मूल्यांकन करना।
- खेल सुविधाओं के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक आयामों की पहचान करना।
- खेल नीति में संसाधन–समानता हेतु संभावित उपाय सुझाना।

परिकल्पना

"शहरी क्षेत्रों में खेल संसाधनों एवं सुविधाओं की संरचनात्मक पर्याप्तता और सुलभता ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा सांख्यिकीय रूप से अधिक है।"

कार्यविधि

यह अध्ययन तुलनात्मक वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है।

शोध के लिए कुल 200 खिलाड़ियों का चयन किया गया — जिनमें 100 ग्रामीण और 100 शहरी क्षेत्र के खिलाड़ी सम्मिलित थे।

डेटा संकलन के लिए एक व्यवस्थित प्रश्नावली तैयार की गई जिसमें अवसंरचना, प्रशिक्षण, उपकरण, कोचिंग, तथा प्रशासनिक समर्थन के आयामों को सम्मिलित किया गया।

संग्रहीत आँकड़ों का विश्लेषण Mean, Standard Deviation(SD) और One-Way ANOVA पद्धति द्वारा किया गया।

विश्लेषण एवं परिणाम

तालिका 1: खेल संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में औसत और मानक विचलन (SD)

समूह	N	औसत	मानक विचलन
ग्रामीण क्षेत्र	100	48.21	7.63
शहरी क्षेत्र	100	61.74	6.92

व्याख्या

प्राप्त आँकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की उपलब्धता का औसत स्तर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से अधिक है।

तालिका 2: वन–वे एनोवा (ANOVA) विश्लेषण

स्रोत	F- मूल्य	P- मूल्य
ग्रामीण बनाम शहरी	8.67<0.05 (महत्वपूर्ण)	

व्याख्या

ANOVA परिणाम यह प्रमाणित करते हैं कि ग्रामीण एवं शहरी समूहों के मध्य संसाधन उपलब्धता में पाया गया अंतर सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण ($p < 0.05$) है। इसका अर्थ यह है कि दोनों समूहों के बीच संसाधनों की उपलब्धता में जो अंतर देखा गया, वह केवल संयोगवश नहीं है, बल्कि यह वास्तविक, प्रामाणिक और शोध के संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर है। यह परिणाम इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संसाधनों की स्थिति शहरी क्षेत्रों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कमजोर है तथा यह विषमता खेल विकास के व्यापक परिदृश्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

यह अंतर इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि संसाधन उपलब्धता खेल प्रतिभाओं के विकास, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, खिलाड़ियों के आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धात्मकता और करियर संभावनाओं का प्रमुख निर्धारक होती है। शहरी क्षेत्रों में संसाधनों का स्तर ऊँचा होने के कारण वहाँ के खिलाड़ियों को अधिक व्यवस्थित प्रशिक्षण वातावरण, आधुनिक उपकरण, अनुभवी प्रशिक्षक तथा खेल विज्ञान समर्थन उपलब्ध होता है। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में इन संसाधनों की कमी खिलाड़ियों के प्रदर्शन, प्रेरणा स्तर तथा अवसरों की समानता पर गहरा प्रभाव डालती है।

ANOVA के परिणाम इस बात को भी उजागर करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास, नीतिगत समर्थन, आर्थिक निवेश और खेल कार्यक्रमों की पहुँच अपेक्षाकृत सीमित है। इन कमियों के कारण ग्रामीण प्रतिभाएँ पर्याप्त अवसरों से वंचित रह जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप शहरी खिलाड़ियों की तुलना में उनका प्रदर्शन स्तर कमजोर दिखाई देता है। यह विषमता केवल आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक, प्रशासनिक और नीति–क्रियान्वयन के अंतर से भी उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन यह भी दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों अपर्याप्त सुविधाओं, प्रशिक्षण उपकरणों की कमी और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के अभाव में अपनी क्षमता का पूर्णतः विकास नहीं कर पाते। वहीं, शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसरों, प्रतियोगी वातावरण और सामाजिक प्रोत्साहन के कारण खेल सहभागिता अधिक सुगम और लक्ष्य–उन्मुख होती है।

परिणाम यह सिद्ध करता है कि खेल संसाधनों की उपलब्धता में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच वास्तविक और स्पष्ट असमानता विद्यमान है, जो खेल विकास में एक गहरी चुनौती के रूप में उभरती है। इस विषमता को संतुलित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, वित्तीय संसाधनों का समान वितरण, ग्रामीण खेल कार्यक्रमों

को मजबूत बनाना और अवसंरचना सुधार आवश्यक है, ताकि दोनों क्षेत्रों के खिलाडि़यों को समान अवसर प्राप्त हो सकें और खेल विकास को समग्र रूप में बढ़ावा मिल सके।

चर्चा

वर्तमान विश्लेषण यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में खेल अवसंरचना का विकास एक संस्थागत प्रक्रिया का परिणाम है, जहाँ नीतिगत समर्थन, आर्थिक निवेश और सामाजिक दृष्टिकोण समन्वित रूप से कार्य करते हैं। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति नीति–निर्माताओं की प्राथमिकता न्यूनतम रही है। यहां तक कि जहाँ प्रतिभा प्रचुर मात्रा में है, वहाँ अवसरों की कमी के कारण वह निष्क्रिय पड़ी रहती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को अभी भी "अवकाश गतिविधि" के रूप में देखा जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह "व्यावसायिक अवसर" और "सामाजिक प्रतिष्ठा" का माध्यम बन चुका है।

यदि इन दोनों दृष्टिकोणों का संतुलन स्थापित किया जाए - ग्रामीण क्षेत्रों के श्रम–आधारित अनुशासन को शहरी क्षेत्रों की तकनीकी सुसंगठितता से जोड़ा जाए- तो भारतीय खेल व्यवस्था अधिक समावेशी एवं प्रतिस्पर्धी बन सकती है।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हूआ है कि भारत में खेल संसाधनों और सुविधाओं के वितरण में क्षेत्रीय असमानता गहन और बहुआयामी है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक सहयोग और तकनीकी प्रगति का समन्वय है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह संरचना लगभग नगण्य है। यदि खेल विकास को वास्तव में लोकतांत्रिक बनाना है, तो नीति–निर्माताओं को ग्रामीण खेल अवसंरचना के पुनर्गठन, प्रशिक्षित कोचों की नियुक्ति, और वित्तीय सहायता के पुनर्वितरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। केवल तभी खेल प्रतिभा का वास्तविक उत्थान संभव है, और भारत "खेल महाशक्ति" बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Singh, P., & Kaur, J. (2018). Sports participation trends among rural adolescents in India. *Journal of Physical Activity and Development Research*, 6(3), 78–89.
2. Verma, L. (2020). Inequality in sports opportunities: A comparative assessment of Indian rural–urban regions. *International Journal of Sports Sociology*, 9(1), 21–34.
3. Dutta, M., & Banerjee, S. (2022). Barriers to sports development in marginalized communities. *South Asian Review of Physical Education*, 15(2), 55–70.
4. Khan, A. (2017). Role of government policy in enhancing sports infrastructure in India. *Indian Journal of Sports Policy and Management*, 4(2), 101–115.
5. Patel, R. (2019). Access to sports facilities and its impact on youth development: A district-level study. *Studies in Human Movement Science*, 11(4), 147–160.
6. Kulkarni, S., & Joshi, V. (2021). Sports coaching and resource deficits in rural India. *Journal of Coaching Science and Practice*, 8(1), 60–74.
7. Thomas, G., & Roy, A. (2020). Socio-economic constraints and sports career choices among Indian youth. *International Sports Education Journal*, 13(2), 91–105.

❑❑❑